(c) The quantities of cotton yarn exported to major importing countries during 1993 is given below.

	(Quantity in million ks)
Bangladesh	41.06
Turkey	12.04
Italy	10.14
Mauritius	9.26
U.K.	8.56

Source: Cotton Textales Export Promotion Councd. EAOIS

(d) The Government has decided to intervene directly by providing upto 20 million Kgs. of hank yarn at a subsidy of Rs. 15 per kg. at an outlay of Rs. 30 crores, to the handloom weavers, through Handloom Agencies. Besides, the Government has also introduced an arrangement for the supply of 75,000 bales of cotton by the Cotton Corporation of India to spinning mills in the State/Cooperative Sector, who in turn; would supply hank yarn to handloom weavers at reduced prices. In addition, the Indian Cotton Mills Federation has also been persuaded to supply some hank yarn at reduce prices. The above measures, which make available a total of 40 million kgs. of hank yarn over a period of five month representing thereby a market intervention of the order of about 20 per cent to handloom weavers at less than market prices, have been taken with a view to ensure availiablity of hank yarn at reasonable prices to handloom weavers. In view of the steps already taken and the desired impact they have had on the market forces, the proposal for levying cess on cotton yarn exports is not being pursued.

(e) Textile Commissioner has not appointed any such expert committee.

Enforcement of textile consumers Production Act

7642. SHRI PRAGADA KOTAIAH: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether stampng of the particulars of yarns and also the varieties of cloth is done according to the provisions of Textile Consumers Protection Act;

(b) if not, the reasons therefor and hwich authority is responsible for the lapse; and

(c) the action taken or proposed to be takken to implement the provisions of the Act in the interests of the consumers of yarn and cloth in the country?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI G. VENKAT SWAMY): (a) and (b) Stamping of the particulars on yarn and cloth as prescribed under the Textiles (Consumer Protection) Regulation 1988 is required to be done by the manufacturing units.

(c) In case of lapses, if any, on the part of the Manufacturing Units; FIRs are filed in the concerned Police Stations for prosecution of the offenders.

सूती धागे का उत्पादन

7643. **श्री राम जेठमलानी** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हथकरघा उद्योग में उपयोग में लाए जाने वाले सूती धागे का देश में पर्याप्त मात्रा में उत्पादन नहीं होता है :

(ख) यदि हां, तो हथकरघा उद्योग में कितने तंतुओं से कितने तंतुओं वाले धागे का उत्पादन किया जा रहा है :

(ग) इसका औसत वार्षिक उत्पादन कितना है ;

(घ) क्या सरकार ने देश के हथकरघा उद्योग की धागे की औसत वार्षिक मांग का मूल्यांकन किया है :

(ङ) यदि हां, तो इसकी मात्रा कतनी है ;

(च) क्या यह भी सच है कि देश में उक्त तंतु-समूह के धागे की मांग के पूरा न होने के बावजूद उसका निर्यात किया जाता है ;

(छ) यदि हां, तो वर्ष 1992-93 के दौरान और अक्तूबर, 1993 से फरवरी, 1994 के दौरान इस धागे की कितनी मात्रा का निर्यात किया गया; और

(ज) सरकार द्वारा धागे की स्वदेशी मांग को पूरा करने की बजाय उसके निर्यात की अनुमति दिए जाने के क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकटस्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) हथकरघा उद्योग में प्रयोग के लिए उत्पादित सूती हैंक यार्न, 6-एस, 10-एस, 20-एस, 26-एस, 30-एस, 40-एस 60 एस, 80 एस, और 100 एस की रेंज का होता है।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान सूती हैंक यार्न का वार्षिक उत्पादन इस प्रकार हुआ :—

वर्ष	मात्रा मि. कि. ग्रा. में
1991-92	328
1992-93	348
1993-94	368 (अनुमानित)

(घ) हथकरघा क्षेत्र में कपड़े का उत्पादन बुनकरों द्वारा अपने घरों में किया जाता है इसलिए विकेन्द्रीकृत हथकरघा उद्योग में सूत की आवश्यकता का अनुमान लगाना आसान नहीं है। सूत की आवश्यकता तैयार उत्पादों की मांग और करघों तथा बुनकरों की उत्पादन क्षमता पर निर्भर करता है।

(ङ) आठवीं योजना के अंत तक सूत की कुल अनुमानित आवश्यकता 561 मिलियन किलोग्राम है।

(च) हथकरघा उद्योग में प्रयोग होने वाले 1-60एस काउंट के सूती धागे के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध है। तथा अग्रिम लाइसेंस योजना के अंतर्गत ही इसका निर्यात किया जा सकता है। जो आयातित कपास के आधार पर होता है।

(छ) सूती धागे की समस्त मात्रा जो 60एस ग्रुप में है तथा सीमा और 100% ई.ओ.यू. के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 1992-93 और अक्तूबर, 1993 से फरवरी 1994 की 5 महीने की अवधि के दौरान निर्यात की गई मात्रा जो निम्नलिखित तालिका में दर्शायी गई है कोन के रूप में थी तथा इसका हथकरघा उद्योग में प्रयोग नहीं किया जाता। अग्रिम लाइसेंस योजना के अंतर्गत किए गए निर्यात के संबंध में उक्त अवधि के दौरान हैंक और कोन यार्न दोनों के निर्यात की अनुमति दी गई जो आयातित कपास के आधार पर है इसी प्रकार 60एस से अधिक ग्रुप के काउंट के यार्न की सीमा और 100% ई.ओ.यू के अंतर्गत किया गया निर्यात है और कोन यार्न का था। अग्रिम लाइसेंस योजना के अंतर्गत और 60 एस से अधिक काउंट धागे के निर्यात के संबंध मे कोन और हैंक यार्न के आंकड़े अलग-अलग उपलब्ध नहीं है। तथापि इस अवधि के दौरान अग्रिम लाइसेंस योजना के अंतर्गत निर्यात की गई सूत की मात्रा का विवरण इस प्रकार है :—

वर्ष	मात्रा मि.कि.ग्रा. में
1992-93	23.50
1एस से 60एस	
60एस से अधिक	1.43
अक्तूबर 93 से	
फरवरी 94	
1एस से 60एस	9.44
60एस से अधिक	1.80

(ज) वस्त्र मंत्रालय सूती धागे के निर्यात के लिए सीमा निर्धारित करने की नीति अपनाता रहा है और ऐसी सीमा निर्धारित करते समय उत्पादन और घरेलू मांग तथा कपास के मूल्यों और इसके उत्पादन, सूत की आवश्यकता तथा हथ-करघा क्षेत्र में सूत की आवश्यकता को मद्देनजर रखा जाता है। इसके अतिरिक्त विश्व बाजारों में अपनी पहचान बनाने और विदेशी मुद्रा अर्जित करने के संबंध में भी विचार किया जाता है। तथापि हथ-करघा उद्योग को संरक्षण देने के लिए 1 से 60 एस काऊंट के हैंक यार्न के निर्यात की अनुमति नहीं दी जाती।

12.00 Noon

SHRI S. JAIPAL REDDY (Andhra Pradesh): Sir, the whole House is greeting the arrival of the Sugar Dada.

MR. CHAIRMAN: I wish you good luck, good fun!

Now statement by Minister correcting answer to Question.

Shri Ghulam Nabi Azad

(The Deputy Chirman in the Chair)

STATEMENT BY MINISTER

Correcting the reply to Starred Question 6 listed for answer in the Rajya Sabha on the 2nd December, 1993 and laid on the table on 6th Dec. 1993

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION AND TOURISM (SHRI GHULAM NABI AZAD): Madam in reply to the Rajya Sabha Starred Question, the statement laid on the Table of the House, stated that:—

"(a): Development of the International Airport at Trivandrum is a continuing process and is taken up in a phased manner, depending upon projected requirement's and availability of resources. International Airports Authority of India (IAAI) strengthening of runway, extension of apon etc., at a cost of over Rs. 18 crores. Besides, it is proposed to instal a state of the art Radar at a cost of Rs. 28 crores and Doppler Very High Omni Range at a cost of Rs 87 lakhs."

By inadvertence, the words "have taken in hand major works such as" which should have appeared before the words 'strengthening of runways' got omitted. This is deeply regretted. The correct reply in respect of part (a) of Rajya Sabha Starred Question No. 6 should read as under:—

"(a): Development of the International Airport at Trivandrum is a contining process and is taken up in a phased manner, depending upon projected requirements and availability of resources. International Airports Authority of India (IAAI) has taken in hand major work such as strenthening of runway, extension of apron etc., at a cost of over Rs. 18 crores Besides, it is proposed to install a state of the art Radar at a cost of Rs. 28 crores and Doppler Very High Omni Range at a cost of Rs. 87 lakhs." (Placed in Library. *See* No. LT-6036/94).

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश): उपसभापति महोदया, मंत्री जी ने जो प्रश्न का उत्तर सही करने का वक्तव्य दिया है उस पर मुझे आपत्ति है। 6 दिसम्बर, 1993 को यह प्रश्न दर्ज था और उस का उत्तर 22, 33 या 24 दिसम्बर तक सत्र चला था उस के अंदर आना चाहिए था। जब सत्र स्थगित हो गया, उसके बाद बजट सत्र हुआ जो 22 फरवरी से करीब पिछले महीने तक चला। आखिर यह संशोधन 22 दिसम्बर तक अगर सही नहीं किया जा सकता तो उस के बाद 3 महीने के अंदर होना चाहिए था। अब तीन महीने बाद उसे आप ठीक कर रहे हैं, यह आपत्तिजनक बात है।

उपसभापति: मंत्री जी, मैंबर साहब का यह ऐतराज है कि दिसम्बर 2, 1993 को राज्य सभा में यह सवाल था, उसके बाद हाउस में इसके जवाब के सुधार में इतना विलम्ब क्यों हुआ?